



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राप्तिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 1975/माघ 8, 1896

No. 38] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 1975/MAGHA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रकाशन संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th January 1975

S.O. 54(E)/18FB/IDRA/75.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) S.O. 72(E)/18FB/IDRA/74, dated the 29th January, 1974, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Hind Cycles Limited, Bombay (Bombay Unit), or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 28th January, 1976.

[No. F. 2/16/73-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूति मंत्रालय

(श्रीधोगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1975

फा० फा० 54(प) / 18 चख/आद० डी० आर० ए० / 75.—यतः उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व श्रीधोगिक विकास मंत्रालय (श्रीधोगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 72(ई) / 18 चख/आद० डी० आर० ए० / 74 तारीख 29 जनवरी, 1974 (जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, घोषित किया है कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या श्रम्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हों) जिनका मेसर्स हिन्द साइक्ल लिमिटेड, मुम्बई (मुम्बई एकक) नामक श्रीधोगिक उपकरण की स्वामी कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे श्रीधोगिक उपकरण या कम्पनी की लागू हों, का प्रबलेन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तद्धीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, वाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ;

और अतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 28 जनवरी, 1976 तक बढ़ाती है।

[सं० फा० 2/16/73-सी०य०सी०]

डी० के० मकपेना, संयुक्त सचिव ।